

# मंत्री व विधायक सदन में बेहतर उपस्थिति व सक्रिय भूमिका निभाएं- भजनलाल

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक विधानसभा परिसर की सत्ता पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। बैठक के शुरू में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड्गाना और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के

- भाजपा विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे का निर्धारित था। बड़ी संख्या में मंत्री व विधायक समय पर नहीं पहुंच पाये, इसलिए बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पाई। पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बैठक स्थल पर समय पर पहुंच गए थे।**

## मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक में अनुशासन व समयबद्धता पर जोर दिया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक ली।

और इसकी कार्यवाही का पूरा सदुपयोग जनहित में किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान के लिए रेलवे क्षेत्र में किए गए 1० हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के बुनियादी ढ ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया। विधायक दल की

बैठक को लेकर एक अहम मुद्दा भी सामने आया। बैठक का समय सुबह 1० बजे निर्धारित था, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। तथापि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं समय पर बैठक स्थल पर पहुंच गए थे।

इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि यदि सभी मंत्री और विधायक समय पर बैठकों में पहुंचेंगे, तो चर्चा भी समय पर और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समयबद्धता सरकार की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और इसे हर स्तर पर अपनाया जाना चाहिए।

## ‘भारत-अमेरिका ट्रेड ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
उसका कहना है कि अमेरिका अक्सर ताकतवर स्थिति से बातचीत करता है और अन्य मामलों में उसने ऐसे समझौते हासिल किए हैं, जिनसे साझेदार देशों के बाज़ार खुले तथा घरेलू नियमों में ढील आई और अमेरिकी निर्यातकों को भारी लाभ मिला। छोटे देशों के साथ हालिया अमेरिकी व्यापार समझौतों का उदाहरण देते हुए जीटीआरआई ने तर्क दिया कि किसी भी भारत-अमेरिका समझौते को वास्तव में पारस्परिक होना चाहिए और केवल अल्पकालिक शुल्क कटौती पर केन्द्रित होने के बजाय, भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या हटाने से भारतीय किसानों को भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी अनाज, डेयरी और पोल्ट्री से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसने यह भी आगाह किया कि शुल्क संरक्षण की जगह ढीले नियामकीय प्रावधान, जिनमें स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानक शामिल हैं, अपनाने से खाद्य सुरक्षा मानक कमजोर हो सकते हैं और वे सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से संवेदनशील सुरक्षा उपाय खत्म हो सकते हैं, जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद बहाल करना कठिन होता है।

निर्यात के मोर्चे पर, जीटीआरआई ने

क्स्त्र, आभूषण, झींगा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊँचे शुल्कों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। उसका तर्क है कि सुनिश्चित और टिकाऊ बाज़ार पहुँच के बिना भारत शुल्क में रियायतें दे सकता है, जबकि उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती जाए। शुल्क से आगे बढ़कर, थिंक टैंक ने बार-बार नियामकीय संप्रभुता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया है और चेतावनी दी है कि बाध्यकारी व्यापार प्रतिबद्धताएँ भविष्य के आर्थिक या भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप नीतियों को पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती हैं।

अंत में, जीटीआरआई ने अमेरिकी प्रणाली के भीतर मौजूद कानूनी और राजनीतिक जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। उसका कहना है कि व्यापार प्रतिबद्धताओं में कांग्रेस द्वारा बदलाव लाया जा सकता है या उन्हें कमजोर किया जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब फास्ट-टैक प्राधिकरण न हो। इससे एक असंतुलन पैदा होता है, जिसमें भारत की रियायतें स्थायी हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी दायित्व घरेलू राजनीतिक उठापटक के अधीन रहते हैं। कुल मिलाकर, जीटीआरआई की आलोचना अस्वीकृति से अधिक सतर्कता पर आधारित है और इस बात पर जोर देती है कि एक टिकाऊ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों, उद्योग और नीतिगत स्वायत्तता की रक्षा करे, न कि अमेरिका को भारी लाभ पहुँचा दे।

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
कारण लोगों को हो रही “भारी असुविधा और पीड़ा” पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के चलते पूरे राज्य में “लगभग 14० मौतें” हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर मौजूदा कानूनों का खुला उल्लंघन करते हुए और “मानवाधिकारों तथा बुनियादी मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह अनदेखी” के साथ संचालित की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 8,1०0 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं।

उन्होंने इस तैनाती की आलोचना करते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को, बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और सिद्ध विशेषज्ञता के, एकतरफा तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह एक “विशेषीकृत, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया” है।

ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा,

“मैं एक बार फिर उस कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को लेकर लिखने के लिए विवश हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से परे जाकर, पश्चिम बंगाल में चल रही

मतदाता सूची की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है।”

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका सुचीबद्ध होने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब आगामी चुनावों से पहले राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका फैसला एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल में व्यापक चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह मामला 4 फरवरी को सुचीबद्ध होने की संभावना है और यदि सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के स्वयं पीठ के समक्ष उपस्थित होने की उम्मीद है।

## मध्यप्रदेश ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
किया। इसके बदले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश को लगभग 3 करोड़ रुपए राजस्व राशि के रूप में भुगतान किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश आयोग के निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, सचिव दीपक सिंह और राजस्थान आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से पीसीबी को मिली प्रतिक्रिया काफ़ी सख़्त रही है। आम राय यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास कोई वैध आधार (कानूनी स्थिति) नहीं है। पीसीबी ने इस बहिष्कार को बाँग्लादेश को दुर्गमैट से हटाए जाने के बाद उसके साथ एकजुटता दिखाने के रूप में पेश किया है, लेकिन इसे एक बनावटी संकट के रूप में देखा जा रहा है।

सदस्य बोर्डों ने कई ऐसे विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, जो इस कदम के पीछे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान की अंडर-1९ टीम ने हाल ही में अंडर-1९ वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला, बिना किसी विरोध या बहिष्कार के बात किए। स्थल असांगति का एक और उदाहरण यह है कि पाकिस्तान की महिला 'ए' टीम उसी दिन (15 फरवरी) को भारत 'ए' के खिलाफ खेलने वाली है और बैंकों में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2०2६ मैच से उसके हटने की कोई योजना नहीं है। चूंकि पुरुष वर्ल्ड कप का मैच कोलंबो, श्रीलंका में एक न्यूट्रल जगह पर होना है, इसलिए बाँग्लादेश द्वारा भारत यात्रा के बारे में बताई गई “सुरक्षा चिंताओं” का पाकिस्तान को स्थिति पर कोई लॉजिकल असर नहीं पड़ता है।

## ‘प्रदेश ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
राजस्व बढ़ाने की गलत नीयत से लागू किया है, जो छोटे खनन लीजधारकों की कमर तोड़ने जैसा है।

यचिका में कहा गया है कि वर्ष 1९75 से 2०1० तक जी.टी. शीट्स के आधार पर खनन क्षेत्रों की सीमाएं (बाउंड्री) तय की जाती थीं। इसके बाद खनन विभाग ने जी.टी.शीट्स को “गूगल अर्थ” से ली गई तस्वीरों पर अपलोड कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में भी कई जगहों पर वास्तविक जमीन स्थिति से करीब १०० मीटर दूरी तक का अंतर था। इस कारण भी कई लीज धारकों के बीच विवाद सामने आया था। अब जो ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का नियम लागू किया जा रहा है, उससे भी करीब 1५-2० मीटर दूरी तक का अंतर सामने आ रहा है। इस समस्या का भी खनन विभाग की ओर से कोई समाधान मुहैया नहीं करवाया जा रहा।

यचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और खनन विभाग सिर्फ ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही लीजधारकों पर जुर्माना तय करके पैनल्टी लगा रहे हैं। यह इसलिए अव्यवहारिक है, क्योंकि ड्रोन सर्वे के आधार पर ही यह तय नहीं किया जा सकता कि किस ब्लॉक में वास्तविकता में कितना खनन किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किस खनन लीज से कितनी मात्रा में बजरी अथवा अन्य पत्थर निकलेगा, इसका मापदंड भी तय नहीं है। ऐसे में ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पैनल्टी किस प्रकार लगायी जा सकती है।

## ‘मुझे नहीं ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
इसके साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यों को निर्लंबित कर दिया गया है, जिनमें से एक वाम दल का सदस्य भी शामिल है। लेकिन, नरेंद्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बावजूद अप्रभावित दिखे। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में स्वयं को माला पहनवाई, और दिन भर टीवी चैनलों पर मोदी, दृप्प और इस ट्रेड डील की तारीफों का दौर चलता रहा कि उन्होंने कितना शानदार काम किया है।

सवाल यह है कि जब विपक्ष के इतने नेता मोदी का सीधे सामना करने और यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया है, तब राहुल गांधी में ही यह साहस है कि वे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करें और गलत को गलत कहें।

# भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
दोनों देश दवाइयों, स्टील, विमानों, तकनीकी उत्पादों और कुछ कृषि वस्तुओं सहित, कई तरह के उत्पादों का पहले से व्यापार कर रहे हैं। सालाना व्यापार का आकार लगभग 1३० अरब डॉलर था, जो न तो बहुत कम था और न ही बहुत ज्यादा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक घोषित ट्रेड डील से ट्रम्प को जरूर झटका लगा होगा।

रूसी तेल खरीदते पर भारत को दंडित करने के अपने फैसले की मूर्खता का एहसास ट्रम्प को तब हुआ होगा, जब उन्होंने देखा कि भारत और ईयू ने लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय व्यापार रूफरेखा पर बातचीत को तेजी से पूरा कर लिया। आखिरकार यह अजीब ही था कि अमेरिका यूरोप में चल रहे किसी और के युद्ध के लिए भारत को सजा दे रहा था, जबकि जो देश वास्तव में रूस से युद्ध के खतरे का सामना कर रहे हैं (यूरोपीय देश), वे खुशी-खुशी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं।

यह समझते हुए कि वह किस स्थिति में फँस गए हैं, ट्रम्प ने फिर एक चाल चली, उन्होंने एकतरफा तौर पर एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा कर दी और साथ ही रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को भी एकतरफा रूप से हटाने का ऐलान कर दिया।

“डैड ट्रम्प” की इस अचानक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के सामने प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें इस घोषणा का स्वागत करना ही पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया की भलाई के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के साथ काम करना कितना सुखद है।

यह पूरा मामला एक बेतुके नाटक का हास्यास्पद तमाशा लगता है। तथाकथित व्यापार समझौते के दोनों पक्ष अब भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

व्यापार समझौता एक गंभीर विषय होता है और इसमें शामिल देशों पर इसके दूरगामी असर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस यह कह दिया जाए कि सभी टैरिफ हटा दिए गए हैं और सामान बिना किसी रुकावट के आया-जाएगा। व्यापार समझौतों में शुल्क संरचनाओं, टैरिफ उद्देश्यों के लिए माल की श्रेणियां और अलग-अलग घरेलू घटक (डोमेस्टिक कंटेंट) से जुड़े विस्तृत प्रावधान होते हैं। ये बातें एक फोन कॉल के तुरंत बाद तय नहीं की जा सकतीं और अनुसंधान पर पेशेवर लोग इन्हें लंबे लंबे समय में तैयार करते हैं।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को एन.एस.यू.आई. की ओर से आयोजित “युवाओं का युद्ध-ड्रस के विरुद्ध” कार्यक्रम में शामिल हुए।

# अमेरिका तय नहीं कर सकता भारत की विदेश नीति- पायलट

## वे एनएसयूआई के “युवाओं का युद्ध-ड्रस के विरुद्ध” में शामिल होने जयपुर आए

जयपुर (कासं), 3 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील, विदेश नीति, टैरिफ, लोकतंत्र और बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चल सकती। यह भारत का अधिकार है कि वह किस देश से तेल खरीदेगा, अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल न खरीदे और वेनेजुएला से खरीदे। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। पायलट ने ये बातें मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से रूबरू होकर कही।

पायलट, एन.एस.यू.आई. की ओर से विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित “युवाओं का युद्ध-ड्रस के विरुद्ध” कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए थे। उनके साथ

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता।**

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनियां, विधायक प्रशांत शर्मा, दीनदयाल बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खटना, वेदप्रकाश सोलंकी,

राकेश पारीक, कांग्रेस नेता अनिल चौपड़ा, वीजीयू के चेयरमैन डॉ. के.आर.बागविया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ औसतन 5 से 7 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 5० प्रतिशत तक किया गया और अब घटाकर 1८ प्रतिशत किया गया है। पायलट ने इसे भारत पर दबाव बनाने की राजनीति बताया।

केन्द्र सरकार के बजट पर निराशा जताते हुए पायलट ने कहा कि इसमें राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है।

# भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

- पर, इस अव्यवहारिक शर्त के अंतर्गत भी व्यापारिक संतुलन बिठाना बहुत कठिन है। भारत, अमेरिका को कम मूल्य के लेवर “इन्टैसिव” प्रोडक्ट्स बेचना है और उनका उत्पादन अचानक एक झटके में बढ़ाना संभव नहीं। जबकि, भारत अगर कुछ हवाई जहाज अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदता है तो अमेरिका का भारत के निर्यात का आंकड़ा अचानक बहुत जल्दी आसमान छूने लगेगा।**

- ट्रंप द्वारा अचानक “ट्रेड डील” की घोषणा करने के कुछ भी कारण हों, पर, भारत के लिए इस डील का अचानक आना और कुछ नहीं, तो एक “डिलोमैटिक” (कूटनीतिक) कामयाबी तो जरूर है ही।**

डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के बाद, इनमें से किसी भी मुद्दे पर शायद ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसा कि ट्रंप ने वादा किया है, रूसी तेल की भारतीय खरीद में कमी के वादे का शायद ही कोई संकेत है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बजाय वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदेगा, जो प्रकृति में रूसी तेल जैसा है और इसलिए भारतीय रिफाइनरियाँ इसे आसानी से अपना सकती हैं।

मान भी लें कि भारतीय रिफाइनरियाँ रूसी तेल की जगह वेनेजुएला का तेल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर भी वेनेजुएला के पूरे तेल उद्योग का उत्पादन भारत की जरूरतों के सामने बहुत कम है। भारत कच्चे तेल का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्टों के अनुसार, वेनेजुएला के तेल उद्योग का कुल उत्पादन भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल से कहीं कम है।

मान लें कि वेनेजुएला का तेल उपलब्ध भी हो, तो उसे समुद्र के रास्ते भारत तक लाना अपने-आप में एक बहुत बड़ा काम है, और वेनेजुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने से पहले इस सब चीजों की व्यवस्था करनी होगी।

सबसे बड़कर, भारत द्वारा अचानक रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने के रणनीतिक प्रभाव भी हैं। भारत रूसी हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर काफ़ी हद तक निर्भर है।

फिर ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक बुनियादी बात है, जिसका दावा ट्रम्प कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत ने अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ शुल्क करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि अमेरिका कम से कम 1८ प्रतिशत टैरिफ बनाए रखेगा। अगर भारत ने ऐसा कोई भी वादा

किया है, तो यह बेहद असामान्य होगा। कोई भी देश दूसरे देश से इसी तरह की छूट के बिना सामानों पर शून्य शुल्क की अनुमति नहीं दे सकता। भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अमेरिकी सामान बिना किसी शुल्क के आए, जबकि उसके अपने उत्पादों पर अमेरिका 1८ या अपनी मज़ी का कोई भी ड्यूटी लगाए।

यह अपनी आर्थिक संप्रभुता छोड़ने जैसा होगा। इसे किसी भी तरह से मुक्त व्यापार समझौता नहीं कहा जा सकता। पिछले एक साल में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की व्यापार बातचीत हो चुकी है, और व्यापार विशेषज्ञों ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए होंगे।

स्थिरता और पारदर्शिता के लिए, इन्हें उचित तरीके से घोषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रम्प ने 2०3० तक भारत और अमेरिका के बीच 5०0 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य घोषित किया है। सन् 2०3० तक न सही, लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार और कुल जीडीपी को देखते हुए इतना बड़ा व्यापार लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर भारत अपने घरेलू नागरिक उद्युधन बेड़े के लिए बोइंग कंपनी से कुछ विमान खरीदता है, तो अमेरिका से आयात का आंकड़ा तेजी से बढ़ जाएगा।

लेकिन भारत के लिए अमेरिका को निर्यात बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। भारत आमतौर पर कम मूल्य वाले उत्पाद, जैसे कपड़ा, चमड़ा, श्रम-प्रधान वस्तुएं, दवाइयां और इसी तरह के छोटे-छोटे मूल्य वाले उत्पाद निर्यात करता है। कम समय में इनकी बिन्नो की तेजी से बढ़ाना मुश्किल साबित हो सकता है।

संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भी इस व्यापार समझौते में शामिल हैं और ये अब भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। यह भारत के लिए